सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com

swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

कानपुर, शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2025
वर्षः 02, अंकः 253, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

» Pg12

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका

इनसाइड जीते-जी न बनी सड़क, निधन के बाद पूरा हुआ... » Pg04

यूपी सरकार का वादा पूरा, विद्यार्थियों के चेहरे खिले

सीएम योगी ने 3.96 लाख छात्रों को दी स्कॉलरशिप

कहा- 2017 के पहले होता था भेदभाव, अब बिना किसी भेदभाव के विद्यार्थियों को मिलता है लाभ

» बोले- गरीब और मेधावी छात्रों को मिलेगा पूरा हक।

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार लाख छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप भेज दी है। सीएम योगी ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह में 3 लाख 96 हजार से अधिक छात्रों को के खाते में 89.96 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी। इस मौके पर उन्होंने कहा विद्यार्थियों को छात्रवृति और शुल्क प्रतिपूर्ति समय से मिल सके इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि यह एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र-छात्राओं की है जिनको यह छात्रवृति बिना किसी हस्तक्षेप के मिलनी है। बता दें कि फरवरी-मार्च में मिलने वाली छात्रवृत्ति इस बार सितंबर में नवरात्र के

अवसर पर छात्रों को दी जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले छात्रवृति वितरण में मनमानेपन और भेदभाव का आरोप लगाते हुए कि 2016 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृति ही नहीं दी गई। 2017 हमारी सरकार आई तो हमने सभी हकदार बच्चों को दो साल की छात्रवृति एक साथ प्रदान की गई। कुछ जनपदों में मुझे शिकायत मिली है कि कुछ संस्थाओं का डाटा लॉक हो गया है और छात्रों को छात्रवृति नहीं मिल पाई। हम आज उस बारे में भी निर्णय लेने वाले है। ऐसे छात्रों की संख्या 5 लाख के करीब है। उनकी छात्रवृति के लिए धन तैयार कर लिया गया है। दीपावली के पहले-पहले उसकी छात्रवृति मिल जाएगी। जिनकी गलती से छात्रवृति नहीं मिली थी, उनकी जवाबदेही भी तय की जा रही है।

समाज कल्याण मंत्री बोले- जिन्हें पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिली, उन्हें भी दी जाएगी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष 60 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी। इस बार जो बच्चे किसी भी कारणवश भले ही वो तकनीकी कारण रहे हों छात्रवृत्ति लेने से वंचित रहे हैं। उन्हें भी इस वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बच्चा छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।

मौलाना ने खुलेआम दी सीएम योगी को दफनाने की धमकी

बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव से इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां आई लव मोहम्मद कार्यक्रम के दौरान एक मौलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। धमकी देने वाले मौलवी की पहचान अशफाक निसार शेख के रूप में हुई है। मंच से दी गई तकरीर में मौलवी ने सीएम योगी को खुलेआम दफनाने की धमकी दी और उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मौलवी ने योगी को माजलगांव की मुस्तफा मस्जिद आने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे वहां आए, तो उन्हें यहीं दफना दिया जाएगा। इस मामले में अब तक माजलगांव पुलिस स्टेशन में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। हालांकि, मौलवी का यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब यह देखना बाकी है कि सीएम योगी को दी गई इस धमकी के मामले में पुलिस क्या कदम उठाती है। फिलहाल यूपी पुलिस की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है।

बड़ी खबर

पिता लालू को किया दरकिनार, भाई तेजस्वी की बढ़ाई टेंशन

तेज प्रताप यादव ने लांच की नई पार्टी, आयोग ने दिया ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह

» कार्यालय संवाददाता, स्वराज इंडिया।

पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी नई पार्टी का नाम 'जनशक्ति जनता दल' है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है। आयोग ने तेज प्रताप की पार्टी को 'ब्लैक बोर्ड' चुनाव चिन्ह अलाट किया है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात ये है कि तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव को ही पोस्टर से गायब कर दिया है। यानी लालू को पोस्टर पर जगह नहीं मिली है।

तेज प्रताप की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के पोस्टर पर महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, डॉ राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को स्थान मिला है। हालांकि राजद से बाहर निकलने के बाद तेज प्रताप कई बार अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के प्रति सम्मान की बात कर चुके हैं। लेकिन पोस्टर पर उन दोनों को जगह नहीं मिला है।

लालू ने तेज प्रताप को किया था राजद से बाहर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर राजधानी पटना की रहने वाली अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसके बाद उनके पिता लालू यादव ने उनको राजद से बाहर कर दिया था।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी सियासी पारी को नई पार्टी के जरिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल बीते कुछ महीने पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को राष्ट्रीय जनता दल से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। जिसके बाद से वो राजद की राह छोड़ अपनी अलग राजनीति की ओर चल पड़े थे। इसी कड़ी में उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है।

तेज प्रताप यादव के राजनीतिक यात्रा की बात करें तो साल 2015 में वो पहली बार वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर विधायक चुने गए थे। पहली बार विधायक बने तेज प्रताप को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार में स्वास्थय मंत्री बनाया गया था। इसके बाद वो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक बने। इस कार्यकाल में तेज प्रताप एक बार फिर बिहार सरकार में मंत्री बने। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप अपनी पुरानी सीट महुआ से लड़ने की तैयारी में हैं।

अखिलेश दुबे की एक और जालसाज़ पीड़िता गिरफ्तार

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

» झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए बनाई साजिश, कारोबारी से वसूले करोड़ों

» ढाई करोड़ की वसूली का काला खेल, युवती ने खोला अखिलेश दुबे का राज

कानपुर। अधिवक्ता अखिलेश दुबे पर गंभीर आरोपों की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। साकेत नगर निवासी होटल कारोबारी सुरेश पाल से ढाई करोड़ रुपये वसूलने के मामले में पुलिस ने बहराइच से उस युवती को ढूंढ निकाला, जिसके जरिए कारोबारी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। सोमवार को कोर्ट में युवती के मजिस्ट्रेटी बयान हुए तो उसने साफ कहा कि ऽअखिलेश भइयाऽ के दबाव में उसने यह झूठा मुकदमा कराया था। युवती ने बताया कि मुकदमा दर्ज न करने पर उसे शहर में रहने न देने की धमकी दी गई थी।

जालसाज पीड़िताओं के शिकंजे में फंसे परिवार झेल रहे गंभीर मुकदमें

बीते सप्ताह स्वराज इंडिया में प्रकाशित हुई एक खबर से तथाकथित गैंग बेनकाब हो गया है

जालसाज पीड़िताएं चला रहीं धन उगाही का रैकेट

एसआईटी जांच में खुल रही परतें, अब कारोबारी के बयान होंगे दर्ज

होटल कारोबारी सुरेश पाल ने बताया कि वर्ष 2021 में अखिलेश दुबे ने वाट्सएप कॉल पर बुलाकर कहा था कि झूठे मुकदमों से बचना है तो रुपये देने होंगे। रुपये न देने पर 2022 में प्रियंका नामक युवती के जरिए उन पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस झूठे मुकदमे ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी और वह परिवार समेत दहशत में शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए।

सुरेश पाल ने बताया कि इसके बाद अखिलेश दुबे ने उन्हें बार-बार अपने कार्यालय बुलाया और गिरफ्तारी न होने का भरोसा दिलाते हुए मुकदमा खत्म कराने का दावा किया। इसके एवज में पहले पाँच करोड़ रुपये की मांग रखी, लेकिन असमर्थता जताने पर ढाई करोड़ रुपये लेने पर तैयार हो गया। यह रकम कई किस्तों में ली गई और इसमें उसका करीबी साथी लवी मिश्रा भी शामिल था, जो बार-बार रुपये लेने आता था। पैसों के लेन-देन के बाद अगस्त 2022 में विवेचना समाप्त कर अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।इतना ही नहीं, कारोबारी ने बताया कि रुपये देने के बाद भी उन्हें बार-बार धमकाया गया कि अगर किसी से शिकायत की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही वजह थी कि वे चुपचाप सबकुछ सहते रहे। लेकिन जब हाल ही में एसआईटी का गठन हुआ और जांच दोबारा शुरू हुई, तब उन्हें न्याय की उम्मीद जगी और उन्होंने पूरा सच सामने रखा। अब युवती के मजिस्ट्रेटी बयान और कारोबारी के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस का मानना है कि पूरा रैकेट और बड़ी साजिश का खुलासा होना तय है।

स्वराज इंडिया ने महीनों पहले अपनी खबर में किया था जालसाज़ पीड़िताओं का जिक्र

मौजूदा वक्त में कानपुर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रकरण जो चल रहा है वह है अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके काले कारनामों कोरा चिट्ठा अब समाज के सामने आ चुका है। अधिवक्ता अखिलेश दुबे के द्वारा पूंजीपति लोगों पर बलात्कार के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते थे और उनको खत्म कराने की अवज़ में करोड़ों रुपए वसूले जाते थे। अब सवाल यह उठता है कि यह महिलाएं कौन होती थीं जो अखिलेश दुबे के एक इशारे पर किसी भी व्यक्ति को अपने मुकदमे का शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाती थीं। तो यह वही जालसाज़ पीड़िताओं का गैंग था जिसका जिक्र महीनों पहले दैनिक स्वराज इंडिया अखबार में किया गया था।

उसके बाद मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक रावत के द्वारा भी कानपुर कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें जालसाज़ पीड़िताओं को लेकर शिकायत की गई थी लिहाजा कहीं ना कहीं दैनिक स्वराज इंडिया के द्वारा छापी गई खबर के बाद शहर में जालसाज़ पीड़िताओं को लेकर हलचल तेज हो गई थी और अब परिणाम शहर के सामने है कि किस तरह से एक आपराधिक किस्म के अधिवक्ता के द्वारा ही इन जालसाज़ पीड़िताओं का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की वसूली की गई है।

कानपुर में अखिलेश दुबे के अलावा एक महिला भी है जो महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले संगठन की आड़ में जालसाज़ पीड़िताओं का एक गैंग चला रही है और लोगों से लाखों रुपए वसूल रही है। दैनिक स्वराज इंडिया की टीम लगातार उस महिला और उससे जुड़ी जालसाज़ पीड़िताओं की पड़ताल में लगी हुई है बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा किया जाएगा।

नर्वल इलाके में बदहाल मिले कई ग्राम सचिवालय

» नर्वल एसडीएम ने गांव सचिवालय में किया औचक निरीक्षण तो खुली पोल

» एडीओ पंचायत भीतरगांव को स्पष्टीकरण

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।नर्वल एसडीएम विवेक मिश्रा ने फार्मर रजिस्ट्रेशन के कार्य में प्रगति जानने के लिए कई गांवों में ग्राम सचिवालयों का औचक निरीक्षण किया। तीनों जगह पंचायत सहायक गायब मिले। एसडीएम के निर्देश पर बीडीओ सरसौल ने एडीओ पंचायत भीतरगांव को स्पष्टीकरण जारी किया है। एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य शासन की प्राथमिकता में है। कार्य में कर्मचारियों की 7 लापरवाही मिली है। लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

एसडीएम विवेक मिश्रा ने ग्राम सचिवालयों का औचक निरीक्षण किया। गांव रातेपुर में कैंप में पंचायत सहायक गैरहाजिर पाए गए। बताया गया कि घर में किसी के बीमार होने के कारण आज लीव पर हैं, कल से उपस्थित होकर सुचारु रूप से कार्य करने को निर्देशित किया गया।

टौंस गांव में पंचायत घर बंद मिला, पंचायत सहायक और सचिव को पंचायत घर कार्य अवधि में गैरहाजिर होने के कारण स्पष्टीकरण के लिए बीडीओ को निर्देशित किया गया।

बरईगढ़ गांव में लेखपाल मिले, पंचायत सहायक के द्वारा इस ग्राम में भी आज फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य नहीं किया जाना पाया गया। सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया कि पारिवारिक रजिस्ट्रर, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन संबंध में प्रतिदिन कैंप लगाना सुनिश्चित करें।

सीएम ग्रिड: दीप सिनेमा चौराहे से सोटे बाबा मंदिर तक बनेगी अत्याधुनिक सड़क

2685.92 लाख की लागत से होगा विकास, भूमि पूजन सम्पन्न

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना (छ्टरू तत्रूष्ठट) के अंतर्गत गुरुवार को दीप सिनेमा चौराहे से लेकर सोटे बाबा मंदिर तक सड़क उन्नयन एवं विकास कार्य का भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर महापौर, नगर आयुक्त, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

कुल 2685.92 लाख की लागत से बनने वाली यह सड़क 1.8 किलोमीटर लंबी और 36 मीटर चौड़ी होगी। इस मार्ग को अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया जाएगा। परियोजना में सुव्यवस्थित पैदल पथ, आधुनिक जल निकासी प्रणाली, स्मार्ट ऊर्जा-संवहनीय स्ट्रीट लाइटें, हरित पट्टी और सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।

महापौर ने बताया कि राज्य सरकार सदैव जनसेवा के लिए तत्पर है और इस प्रकार की महत्वाकांक्षी

योजनाएं न केवल सुगम आवागमन सुनिश्चित करती हैं बल्कि विकास की नई पहचान भी बनाती हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से

नागरिकों को सुदृढ़ सड़क अवसंरचना, सुरक्षित पदयात्रा पथ, हरित वातावरण और बेहतर यातायात व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

यह परियोजना नगर के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक सड़क सुविधा उपलब्ध होगी।

बर्रा थाना क्षेत्र में नई चौकियों की मांग

सपा नेता और पार्षद अर्पित यादव के प्रयासों से बढ़ेगी सुरक्षा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।शहर दक्षिण के घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर समाजवादी पार्टी नेता ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस कमिश्नर से थाना बर्रा क्षेत्र में नई चौकियों की स्थापना की मांग उठाई है।बर्रा थाना क्षेत्र फिलहाल व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें चौकियों की संख्या अपर्याप्त है। दामोदरनगर, कटही और जरौली जैसे क्षेत्रों में आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण गश्त और निगरानी प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, दामोदरनगर में एक नई चौकी तथा विश्व बैंक कॉलोनी के सभी 12 ब्लॉकों को अलग चौकी क्षेत्र में शामिल करने की मांग रखी गई है।

इसी तरह यादव मार्केट और जनता नगर चौकियों के परिसीमन के बाद एक और नई चौकी के गठन का सुझाव दिया गया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो बर्रा थाना क्षेत्र में मौजूदा तीन चौकियों की संख्या बढ़कर पाँच हो जाएगी।सपा नेता का कहना है कि यह कदम न केवल पुलिस गश्त को सुचारु करेगा बल्कि स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुरक्षा का अनुभव भी देगा। क्षेत्रीय जनता ने भी इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

पूर्व में रहे अफसरों ने नहीं समझा था सेनानी का दर्द

जीते-जी न बनी सड़क, निधन के बाद पूरा हुआ सेनानी का सपना!

एसडीएम संजीव दीक्षित ने लिया संज्ञान, 15 अगस्त को सम्मान समारोह में एसडीएम को सुनाई थी अपनी पीड़ा

सड़क निर्माण कार्य शुरू, विवाद की आशंका के चलते मौजूद लेखपाल व पुलिस(

» रिजवान कुरैशी, स्वराज इण्डिया।

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर के चंद्रपुरा गांव निवासी 107 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 राजाराम द्विवेदी की बरसों पुरानी ख्वाहिश उनके जीते-जी पूरी न हो सकी। कई बार अपने घर तक पक्की सड़क की मांग करने वाले सेनानी की यह आस उनके निधन के बाद पूरी हुई। गुरुवार को जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाकर सड़क निर्माण शुरू कराया, तो परिजनों और गाँव वालों की आंखें भर आईं।

दरअसल, अपने जीते जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजाराम द्विवेदी ने कई बार इस मांग को उठाया था। बीते 15 अगस्त को जब नए आए उप जिलाधिकारी संजीव दीक्षित ने उनके घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मेरे घर तक सड़क बनवा दीजिए। एसडीएम ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित विभाग को आदेश दिए. लेकिन विपक्षीगण रजौल, रामू और श्यामसुंदर पुत्र स्व. रामनाथ के कब्जे के कारण काम अटक गया। इसके बाद सेनानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। हाल ही में उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों और परिजनों ने इस मांग को दोहराया। मामला मीडिया में आने के बाद एसडीएम संजीव दीक्षित ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाया और सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया। काम शुरू होते ही माहौल भावुक हो उठा। परिजनों ने कहा-काश यह काम उनके जीते-जी हो जाता। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

एसडीएम की कार्यशैली बनी चर्चा का विषय

चार्ज संभालते ही उप जिलाधिकारी संजीव दीक्षित सुर्खियों में आ गए हैं। फरियादियों की सुनवाई का उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग है। नरमी और सख्ती दोनों का संतुलन उनके कामकाज में साफ झलकता है। तहसील के अफसर और कर्मचारी भी उनकी कार्यशैली का असर महसूस कर रहे हैं। ढिलाई बर्दाश्त न करने वाले एसडीएम ने जिम्मेदारों की चूड़ी कस दी है। यही वजह है कि बिल्हौर तहसील की बिगड़ी व्यवस्था अब पटरी पर आती नजर आ रही है। समय से दफ्तरों में न आने वाले अब राइट टाइम दिख रहे हैं।

...तो क्या बरौली स्कूल तक सड़क बनवाएंगे एसडीएम दीक्षित?

बिल्हौर। अपने काम के अंदाज़ से लोगों का दिल जीतने वाले एसडीएम संजीव दीक्षित से उच्च प्राथमिक विद्यालय बरौली व उसमे पढ़ने वाले बच्चे और टीचर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब उनके स्कूल तक पक्की सड़क का सपना पूरा हो जाए। करीब 22 साल पहले हुई बरौली स्कूल की स्थापना के बाद से आज तक वहाँ पहुँचने के लिए पक्का रास्ता नहीं बन सका। यह स्थिति तब है जब बेसिक शिक्षा, तहसील व जिले के अधिकारियों और सरकार में सांसद विधायक की निगाह में है। वहीं प्रति वर्ष स्कूलों के कायाकल्प पर लाखों-करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। फिर भी इस तरफ से बेरूखी न जाने क्यों है। इस मुद्दे को स्वराज इंडिया ने पहले भी प्रमुखता से उठाया था।

तत्कालीन एसडीएम रश्मि लांबा ने इसका संज्ञान लेकर गांव में निरीक्षण किया था और चौपाल भी लगाई थी, मगर सड़क का निर्माण अधूरा ही रह गया। बाद में भाजपा नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष जे.पी. कटियार ने भी मामले को गंभीरता से लिया और एमएलसी अरुण पाठक को पत्र लिखकर गुहार लगाई। इसके बावजूद तस्वीर जस की तस है। हालत यह है कि आज भी बच्चों और शिक्षकों को खेतों से होकर स्कूल पहुँचना पड़ता है। रास्ते में सांप-बिच्छू और जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। ऊपर से स्कूल की जर्जर इमारत किसी हादसे को दावत देती नज़र आ रही है। ऐसे माहौल में बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इससे खंड शिक्षा अधिकारी और तहसील प्रशासन के अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है। उनके दफ्तरों तक बेहतरीन सड़कें बनी हैं। दफ्तर ठीक है लेकिन बरौली स्कूल की दशा आज भी बदहाल है। कार्यालकल्प की बाट जोहते बरौली स्कूल को एसडीएम संजीव दीक्षित का इंतजार है। ताकि वह उनके बीच जाकर उनके दर्द और अधूरे सपने को पूरा कर पाएं। वरना कहीं ऐसा न हो कि कुछ समय बाद बच्चों की संख्या की कमी के चलते यह स्कूल ही बेमौत मारा जाए।

मुझे नही जीना मर जाने दो!

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। शुक्रवार सुबह जीटी रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मानसिक रूप से अस्थिर एक महिला अचानक बीच सड़क पर जाकर लेट गई। तेज रफ्तार वाहनों को देखकर लोगों में दहशत फैल गई।

एक रहागीर ने हिम्मत दिखाते हुए महिला को साइड में किया और उसकी जान बचाई। महिला रहागीर से बार-बार कहती रही मुझे नही जीना मर जाने दो।

किशोरी को फोन पर परेशान करने वाला शोहदा गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। थाना क्षेत्र के ग्राम बीबीपुर में एक किशोरी को फोन पर परेशान और छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी अंशु सैनी पुत्र कुलदीप सैनी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि अंशु सैनी लगातार उनकी पुत्री को परेशान कर रहा था। सूचना पर थाना बिल्हौर की मिशन शक्ति टीम ने मामले की जांच की।

पुलिस की जांच के दौरान आरोपी विवाद करता पाया गया और पुलिस के समझाने के बावजूद शांत नहीं हुआ।

इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अंशु सैनी को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया।

अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर चुनावी दांव पर उतरे श्रीराम गौतम

समर्थकों के साथ पहुंचे बिल्हौर कचहरी, विशेष योजनाओं की घोषणा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के लिए ताल ठोक रहे कानपुर के वरिष्ठ वकील श्रीराम गौतम ने अपनी टीम के साथ गुरुवार को कचहरी का दौरा कर अधिवक्ताओं से समर्थन मांगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

गौतम ने कहा कि कानपुर में पुलिस बेलगाम है वकीलों को टारगेट कर कार्रवाई कर रही है।प्रदेश मे अधिवक्ताओं पर आए दिन हमले होते रहते हैं। अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर होना चाहिए, लेकिन अक्सर कमेटी अपने फायदे के लिए 6 से 8 साल तक चुनाव स्थगित कर देती है।हम जीतेंगे तो समय पर चुनाव कराने का कार्य करेंगे,जो न्याय संगत है। उन्होंने नए अधिवक्ताओं के लिए भी योजनाओं का जिक्र किया। उनका कहना है कि नए अधिवक्ताओं को कचहरी में अपनी पैठ बनाने में समय लगता है, इसलिए उन्हें 5000 रूपये प्रति माह देने की पहल की जाएगी। वहीं 60 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं के लिए, जो काम करने में असमर्थ हैं, 10000 हजार प्रतिमाह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं पर भी गौतम ने ध्यान दिया। गर्भवती महिलाओं को वकालत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अक्सर उन्हें रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को 15000 रूपये प्रतिमाह देने के लिए आवाज उठाएंगे।और कहा प्रथम (1) वरीयता मत देकर हाथों को मजबूत करें।

श्रीराम गौतम की ये घोषणाएं न केवल अधिवक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देने का संकेत देती हैं, बल्कि आगामी चुनाव में उनके समर्थन को भी मजबूती देंगी। इस दौरान एडवोकेट नवीन चंद्र गौतम, दीप सिंह, जीतेन्द्र दोहरे, शारदा गौतम, राहुल वर्मा, गौरव चतुर्वेदी, दीपक, विनय गौतम समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

सम्पादकीय

गंभीर पहल से ही होते हैं युद्ध समाप्त

संयुक्तराष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का जैसा अगंभीर व असामान्य व्यवहार नजर आया, उससे कहीं से नहीं लगा कि वे विश्व की एक महाशक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया में युद्धों को समाप्त करने के लिये सिर्फ बयानबाजी नहीं, ठोस रणनीति व गंभीर प्रयासों की जरूरत होती है। संयुक्त राष्ट्र में डोनॉल्ड खुद को लगातार जबरदस्ती एक शांति के मसीहा के तौर पर पेश करते रहे हैं। उन्होंने दावा दोहराया कि उनके नेतृत्व में दुनिया में सात युद्धों को समाप्त किया गया। दावा कि उन्होंने संघर्ष को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। जबकि इसके विपरीत उनके भाषण का सार कुछ और ही दर्शाता है। साफ नजर आया कि एक ऐसा नेता जो स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक सहयोग के स्तंभों को ही कमजोर कर रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूंजीपति सरोकारों के अनुरूप उन्होंने 'जलवायु परिवर्तन को अब तक का सबसे बड़ा धोखा' बताकर खारिज कर दिया। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों से पूरी दुनिया में जन-धन की व्यापक क्षति हो रही है। इसके चलते सूखे, बाढ़ व विनाशकारी तूफानों से पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा खतरे में नजर आ रही है। जो मानव जीवन को लगातार संघर्षमय बना रहे हैं। ट्रंप का शांति बनाये रखने के दावे करना और जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को नकारना, उनके विरोधाभासी व्यवहार को ही दर्शाता है। साथ ही उनकी बयानबाजी के खोखलेपन को ही उजागर करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कि उन्होंने विश्वव्यापी प्रवासन को 'राष्ट्रों को नष्ट करने वाली' शक्ति बताकर निंदा की, जो मानवता के खिलाफ दुर्भावना ही कही जाएगी। बेहतर भविष्य और सुखमय जीवन की तलाश में प्रवासन सदियों से मानव इतिहास का हिस्सा रहा है। जिसने विभिन्न समाजों को नया आकार दिया है और प्रगति को नई गति दी है।निस्संदेह, प्रवासियों को खतरे के रूप में पेश करना जेनोफोबिया को बढ़ावा देना है। जो वैश्विक समुदायों को विभाजित करने की कुत्सित कोशिश है। ऐसे संघर्ष को रोकने के बजाय इस तरह की गैरजिम्मेदार बयानबाजी सामाजिक आक्रोश और विभाजन को ही जन्म देगी। कालांतर ये विकसित राष्ट्रों में आए प्रवासियों के विरुद्ध नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देगा। निस्संदेह, प्रवासियों के लिये अपने दरवाजे बंद करने से शांति सुनिश्चित नहीं होती। आज जब आधुनिक तकनीक व संचार क्रांति के चलते दुनिया के एक गांव में तब्दील होने की बात कही जाती है तो यह सोच नितांत अतार्किक व मानवीय मूल्यों की विरोधी ही है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र पर ट्रंप का हमला करना और इसे 'अप्रभावी और पाखंडी करार देना'- उनके कथित शांतिदूत होने के दावे को कमजोर करता है। माना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आज के संघर्षरत विश्व में यह एकमात्र वैश्विक निकाय है,

नेताओं-अभिनेताओं के कुनबे में कुचलता हुनर

डा0 जोगिन्दर सिंह

भारत के लोकतंत्र और फिल्म उद्योग में परिवारवाद इस कदर गहराया है कि सत्ता, अवसर और पहचान कुछ चुनिंदा परिवारों तक ही सीमित होकर रह गई है, जिससे आम जनता को बराबरी का हक नहीं मिल पाता। अपने देश में...भारत के लोकतंत्र और फिल्म उद्योग में परिवारवाद इस कदर गहराया है कि सत्ता, अवसर और पहचान कुछ चुनिंदा परिवारों तक ही सीमित होकर रह गई है, जिससे आम जनता को बराबरी का हक नहीं मिल पाता।अपने देश में लोकतंत्र है। इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन यहां अब भी सामंतवाद की जड़ें बेहद गहरी हैं। इसका उदाहरण राजनीतिक दलों को देखकर मिलता है। फिल्मी दुनिया, जो अपने को देश-काल की सीमाओं से परे बताती है, में भी ऐसा ही है।अपने देश के अधिकांश राजनीतिक दलों की अगली पीढ़ी के रूप में नेताओं के बाल-बच्चे ही दिखाई देते हैं। पिता ही पुत्र का राजा की तरह राज्याभिषेक कर देते हैं। जिस तरह राजा की गद्दी उसके बेटे को ही मिलती थी, राजनीति में भी इसे बखूबी देखा जा सकता है।

हां, कभी-कभार इसमें बेटियों, बहनों या पत्नियों को शामिल कर लिया जाता है। यानी कि हर हाल में सत्ता चाहिए। वह अपने बाद भी हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसमें भी वारिस या उत्तराधिकार का नियम लागू है। बिहार के एक वरिष्ठ नेता, जो जयप्रकाश नारायण के कांग्रेस विरोधी आंदोलन की नैया पर सवारी करते हुए, राजनीति के शिखर पर आए, ने एक बार कहा था कि यदि हम अपने बच्चों की मदद नहीं करेंगे, तो क्या हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। इसी तरह एक बार बोले थे कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री न बनाएं, तो क्या तुम्हारी पत्नी को बनाएं। उत्तर प्रदेश की एक पार्टी के बाईस परिवार जन राजनीति में बताए जाते हैं। हाल ही में फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि बिहार की राजनीति में अनेक दलों में परिवार के सत्ताईस प्रतिशत लोग हैं।

अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने में कोई भी दल पीछे नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा बंगाल कहीं भी देख लीजिए। यानी कि बात तो आम जनता की होती है, लेकिन उसके प्रतिनिधित्व के नाम पर दलों के उच्च पद हमेशा परिवार जनों को ही मिलते हैं। ऐसा क्यों मान लिया जाता है कि नेतृत्व देने की सारी क्षमता, सिर्फ राजनेताओं के परिवारों के पास ही होती है। दरअसल तो यह शक्तिपूजक देश है। एक बार जो ताकत का स्वाद चख लेता है, वह उसे कभी खोना नहीं चाहता। राजनीति से ज्यादा शक्ति भला और किसके पास हो सकती है। बात चाहे जितनी गरीबी और साधनहीनता की की जाए, बाय द पीपुल, फार द पीपुल, आफ द पीपुल की हो, हर बात पर लोकतंत्र और सबकी बराबरी का ढोल पीटा जाए, असली मकसद साधनों का बेहिसाब जुगाड़ ही होता है। वर्ना तो ऐसा कैसे होता है कि राजनीति में आते ही एकाएक लोगों की आर्थिक स्थिति छलांगें मारती आकाश छूने लगती है।कहा ये जाता है कि ये सारी आर्थिक ताकत भी समर्थक जुटाते हैं। साइकिल पर चलते नेता जी अचानक मर्सिडीज और पोर्श में नजर आने लगते हैं। और जब यह हर तरह की बेशुमार ताकत एक बार मिल गई, तो भला कौन इसे जाने दे। लोगों के बीच वर्षों लगाकर, जो जगह बनाई उसे किसी बाहर वाले को क्योंकर हड़पने दिया जाए। इसलिए सबसे पहले अपने ही बाल-बच्चों, अन्य परिवारजनों का ख्याल आता है।

पेपर लीक श्रृंखला से आक्रोशित बेरोजगार युवा

बेरोजगारी

केसी त्यागी

उत्तराखंड स्थापना आंदोलन के दौरान रोजगार प्रमुख मुद्दों में शामिल था ताकि नये राज्य में युवाओं का भविष्य बेहतर हो। लेकिन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होना तंत्र से भरोसे को डिगाता है।उत्तराखंड राज्य के आंदोलन को मातृशक्ति और युवा शक्ति का आंदोलन कहा गया था। एक स्वयंस्फूर्त आंदोलन में युवाओं की ऐसी भागीदारी थी, जिसमें वे निजी हितों को तिलांजलि देकर बड़े उद्देश्य के लिए आंदोलन में कूद पड़े थे। राज्य स्थापना के आंदोलन के पीछे कई पहलुओं को देखा गया, लेकिन दशकों से चले आ रहे आंदोलन को नब्बे के दशक में चिंगारी रोजगार के मसले पर ही मिली थी। युवाओं ने महसूस किया था कि जिस आरक्षण को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, वह उनके रोजगार छीन लेगा।राज्य स्थापना के 25 साल बाद अब फिर युवा उसी तरह सड़कों पर उतरा है। बेशक उसका यह आंदोलन किसी आरक्षण या किसी तकनीकी आधार के विरोध पर नहीं, लेकिन उत्तराखंड में फिर से पेपर लीक की घटना से वह आहत हुआ है।

उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ है। परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट के अंदर पेपर के तीन पेज सोशल

मीडिया पर वायरल हो गए। हालांकि पेपर लीक होना या भर्ती घोटाला इस राज्य के लिए नई बात नहीं रही। राज्य बनने के साथ ही ऐसी घटनाएं समय-समय पर होती रही हैं। राज्य की शुरुआत के साथ ही 2003 में पटवारी भर्ती घोटाला और दारोगा भर्ती घोटाला सामने आये। पेपर लीक का यह पहला मामला नहीं। साल 2021 में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसमें कई आरोपी गिरफ्तार हुए तथा जांच के आदेश दिए थे। राज्य में पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी जैसी कई परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। वन दारोगा भर्ती में भी पेपर लीक व ऑनलाइन नकल के आरोप लगे। जांच हेतु राज्य सरकार ने विशेष जांच दल गठित किया।2023 में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित घोटालों के खिलाफ छात्रों के जगह-जगह विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार 'उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023' लेकर आई थी। तब इसे पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सबसे सख्त कानून बताया गया। इसमें ऐसी कड़ी धाराएं थी जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को सोचने पर विवश करें। लेकिन हाल ही में फिर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा दौरान पेपर लीक की बात सामने आई है, जिसने सबको चौंकाया। हर कोई हैरान है कि कड़े कानून और समय-समय पर कार्रवाई होने के बावजूद ऐसे तत्वों पर फर्क नहीं पड़ा है।निश्चित ही ऐसे काम को अंजाम देने वाली एक बड़ी लॉबी सक्रिय है, और इस पूरे तंत्र से निपटना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे तत्वों का फैलाव इतनी दूर तक है कि सरकार का मजबूत तंत्र उनसे निपट नहीं पा रहा है।

इरफान की दशहरे से पहले हो सकती है रिहाई

सपाइयों ने कहा- न्याय की हुई जीत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत तीन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इरफान और रिजवान ने 2 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के बंगले पर समर्पण किया था। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। तब से ही दोनों जेल में बंद हैं। दोनों के खिलाफ दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है।

अब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी जमानत मिलने पर दो साल नौ माह बाद दोनों की जेल से रिहाई संभव हो सकेगी। जाजमऊ थाने में नजीर फातिमा का घर जलाए जाने की घटना के बाद इरफान व उनके भाई रिजवान समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद कई और मुकदमे भी दर्ज हुए। इन मुकदमों के आधार पर इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मो. शरीफ, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मुर्सलीन खान उर्फ भोलू, मो. एजाज उर्फ अज्जन के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

इस मुकदमे में सातों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट भेज दी गई है। सातों अभियुक्तों में से इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल और रिजवान व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में बंद हैं। इसके अलावा अन्य चारों हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो चुके हैं। मुकदमे में 17 सितंबर को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में सभी सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं।

इरफान सोलंकी का अंतरजनपदीय स्तर का संगठित गिरोह है। यह अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाता है और गिरोह के सदस्य अवैध धन से ऐशोआराम की जिंदगी गुजारते हैं। मारपीट, आगजनी, धोखाधड़ी करके जमीन कब्जाना, रंगदारी वसूलना आदि गिरोह के काम हैं।

हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से यही तर्क रखा गया था कि आरोपी सेशन कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में आरोप तय नहीं होने दे रहे। बेवजह के प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे को लंबित कर रहे हैं। जेल से रिहा हुए, तो मुकदमे को और लंबित रखेंगे। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच 17 सितंबर को सभी आरोपी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में आरोप तय हो गए। पेशी के दौरान इरफान के चेहरे और बातों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसी के बाद से इरफान और रिजवान की जल्द रिहाई के संकेत मिल गए थे।

हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद गैंगस्टर कोर्ट में जमानतें दाखिल करनी होंगी। कोर्ट जमानतगीरों का सत्यापन कराएगी। इसके बाद रिहाई परवाना जारी होगा और रिहाई हो जाएगी। माह के चौथे शनिवार और रविवार को अदालत बंद रहेगी। सोमवार और मंगलवार को काम होगा। इसके बाद विजयदशमी की छुट्टी हो जाएगी। अगर इस दौरान रिहाई परवाना जारी नहीं हुआ, तो रिहाई छुट्टियों के बाद ही हो सकेगी।

जाजमऊ की डिफेंस कालोनी स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर पर 7 नवंबर 2022 को आग लगाई गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व साथियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इरफान ने भाई रिजवान के साथ 2 दिसंबर 2022 की सुबह पुलिस कमिश्नर के बंगले पर समर्पण कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने 7 जून 2024 को इरफान, रिजवान, शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटेवाला को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। अपील स्वीकार होने पर 14 नवंबर 2024 को इरफान को जमानत मिल गई थी। अन्य मुकदमों में भी इरफान-रिजवान को जमानत मिल चुकी थी सिर्फ गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत मिलने का इंतजार था।

छह जगह शुरू हुई टिकटों की ऑफलाइन बिक्री, 100 से लेकर 499 तक के हैं टिकटे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। ग्रीनपार्क स्टेडियम में होने वाले इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के मैचों के लिए शुक्रवार से छह अलग-अलग स्थानों पर ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। टिकटों की कीमत 100 रुपये से 499 रुपये तक है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है।

ग्रीनपार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले तीनों वनडे मैच के लिए मंगलवार रात साढ़े नौ बजे से बुक माय शो पर टिकट की ऑनलाइन शुरू की गई थी। बुधवार तक करीब एक लाख रुपये के टिकट बिक गए थे। शहर में क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए शुक्रवार से अलग-अलग स्थान पर ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि उप्र क्रिकेट एसोसिएशन शुक्रवार से ग्रीनपार्क स्टेडियम सहित शहर के छह स्थानों पर सुबह 11 बजे से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हुई है।

यहां 100 से लेकर 499 रुपये तक के टिकट मिल रहे हैं। पवेलियन बालकनी, वीआईपी पवेलियन की टिकट 499 रुपये की है। पवेलियन ग्राउंड की टिकट 250 रुपये, सी बालकनी की टिकट 200 रुपये तथा बी जनरल व सी स्टाल की टिकट 100 रुपये की हैं। ग्रीनपार्क के अलावा बाटू टेलीफोन प्वाइंट लाजपतनगर और गोविंदनगर, यूनीसेफ मोबाइल लालबंगला, स्माइल स्टोर बिरहाना रोड, हीरा टेली कम्युनिकेशन कल्याणपुर, ड्रीम्स टेलीशॉप यशोदानगर से टिकट ब्रिकी हो रही है।

छिनौती: महिलाओं से तबाड़तोड लूट,मंगलसूत्र तोड़कर भागे लुटेर

कानपुर। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार रात हरबसपुर गांव के पास हाईवे पर सामने से आए बाइक सवार दो लुटेरों ने झपट्टा मारकर बाइक सवार महिला के गले से मंगलसूत्र लूटा लिया। पीड़ित की बाइक का संतुलन बिगड़ने से महिला व बच्चे गिरकर घायल हो गए। गीतानगर नगर निवासी रोशनी पति चंदन, दो बेटों वंश व अंश के साथ बाइक से अपने मायके बिधनू के कठारा गांव जा रही थीं।कानपुर-सागर हाईवे पर हरबसपुर गांव के पास बाइक सवार दो लुटेरे बाइक पर पीछे बैठीं रोशनी का मंगलसूत्र तोड़कर रमईपुर की ओर भाग निकले। महिला बच्चों समेत बाइक से हाईवे पर गिरकर घायल हो गईं। राहगीरों ने घायल महिला और बच्चों को सीएचसी पहुंचाने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पति चंदन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है।वहीं, मंगलवार की रात चकेरी थाना क्षेत्र में भी होने से बचा। पल्सर सवार लुटेरों ने चलती स्कूटी पर पति के साथ पीछे गोद में सात माह की बेटी को लेकर बैठी महिला के झपट्टा मारकर बाएं कान का झाला लूट लिया।

आवश्यक सूचना

मैं विमला पत्नी स्वर्गीय बैजू यह सूचित करती हूँ कि मेरा पुत्र प्रदीप कुमार व पुत्रवधू लक्ष्मी आए दिन गाली-गलौज व मारपीट कर मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं। तथा इनके चालों चलन भी ठीक नहीं है अत: मैं आज से इन्हें अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करती हूँ। आज से मेरा व मेरे परिवार का इनसे कोई संबंध या लेन-देन नहीं रहेगा। ये अपने अच्छे-बुरे के स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विमला पत्नी स्वर्गीय बैजू
ग्राम प्रधानपुर, थाना शिवराजपुर,
तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर

कुत्ता पालने वाले गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर मंझरिया की दुखद मौत

नाखून के खरोंच को न माना गंभीर — एक बड़ा चेतावनी संदेश

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया अहमदाबाद (गुजरात)

पुलिस अमले को झकझोर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है – अहमदाबाद के एक पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मंझरिया का निधन रेबीज़ (पशु पागलपन रोग) के कारण हो गया। यह मौत एक मामूली-सी घटना से शुरू हुई – उनके पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते की नाखून की खरोंच।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इंस्पेक्टर मंझरिया नियमित रूप से अपने पालतू कुत्ते को रेबीज़ वैक्सीनेशन करवाते थे। घटना 5 दिन पहले हुई थी, और शुरुआत में उन्हें इसकी गंभीरता का अहसास नहीं हुआ। उन्होंने खरोंच को मामूली समझा और तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं ली। बाद में स्थिति बिगड़ी, उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने पाँच दिनों की जंग हार दी। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि बीमारी की प्रगति बेहद तीव्र थी, और अंतिम समय में मंझरिया को अस्पताल के बिस्तर से बांधना भी पड़ा क्योंकि वायरस उनके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर रहा था।

इस घटना ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया कि रेबीज़ रोग पर लापरवाही, कितनी भी सावधानी बरती हुई हो, घातक हो सकती है। विशेष रूप से यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारंपारिक धारणा — अगर काटा नहीं, तो खतरा नहीं — को चुनौती देता है।

पुलिस इंस्पेक्टर मंझरिया का यह दुखद निधन सिखाता है कि रेबीज़ एक भयंकर रोग है, जिसे हल्के मामले मानना खतरनाक है। चाहे काटा हो या खरोंच लगी हो — अगर संदेह हो, तुरंत चिकित्सकीय हस्तक्षेप आवश्यक है। देश में कुत्ते काटने / काटे जाने की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं, जो यह संकेत देती हैं कि हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और जनजागरूकता पर बल देना होगा।

देश में कुत्ते काटने और रेबीज़ से जुड़ी अन्य प्रमुख घटनाएँ

2025, कर्नाटक (दावनगेरे)एक 4 वर्षीय लड़की को आवारा कुत्ते ने काटा था। लगभग 4 महीने चलने वाले इलाज के बाद लड़की की मौत हो गई।

भारत (विभिन्न राज्यों) आवारा कुत्तों द्वारा काटने की संख्या में वृद्धि भारत में आवारा कुत्ते जनित काटने मामलों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर संक्रमित काटने / रेबीज़ की चुनौतियाँ भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कुत्ते काटने के मामलों में हर वर्ष लाखों की संख्या है, और ये मामलों में रेबीज़ का जोखिम बना रहता है।

भारत (मृत्यु-कुत्ते हमला) fatal dog attacks भारत में ऐसे कई मामले हैं जहाँ लोगों की मौत कुत्तों द्वारा हमला करने के कारण हुई है। उपर्युक्त उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि कुत्ते कटने या संपर्क में आने वाली चोटें कभी हल्के में नहीं ली जानी चाहिए।

कुत्ते के काटने या खरोचने पर– क्या करना चाहिए, क्या नहीं

1. छोटा या हल्का खरोंच भी लिया नहीं जाना चाहिए — यदि खरोंच या काटने की स्थिति हो, तुरंत घाव को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोएं।

2. तत्काल चिकित्सा सलाह लें — पशु काटने या खरोंच के बाद तुरंत चिकित्सालय जाएँ और पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (टीकाकरण) शुरू करवाएं।

3. पूरी वैक्सीन श्रृंखला पूरी करें — यदि डॉक्टर उपयुक्त निर्देश दें, तो सभी निर्धारित डोज़ अनुकूल समय पर लें।

4. पालतू जानवरों की नियमित जाँच और टीकाकरण — आपके पालतू कुत्ते को डॉक्टर द्वारा टीकाकरण करवाते रहें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जोखिम से सुरक्षित हैं।

5. संक्रमित जानवरों से दूरी बनाए रखें — विशेषकर बिना वैक्सीन या अस्वस्थ दिखने वाले जानवरों के संपर्क से बचें।

6. जानकारी फैलाएँ — ये घटना बताती है कि आम लोगों में जागरूकता बहुत कम है — स्कूल, समाज, मीडिया के माध्यम से सही जानकारी देना आवश्यक है।

आई लव मोहम्मद पर बरेली में बवाल

» बैनर लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, तोड़फोड़... लाठीचार्ज; तौकीर रजा नजरबंद

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बरेली। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के अलग-अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर बैनर लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। साथ ही मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर लिया गया है।श्यामगंज में पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान एसपी क्राइम से नोकझोंक भी हुई, लेकिन जुलूस के रूप से भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती गई। स्थिति को देखते हुए श्यामगंज में पुलिस ने दुकानें भी बंद करा दीं। नौमहला मस्जिद के बाहर भी सैकड़ों लोग जुटे। लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के एलान के बाद से शहर में गहमागहमी का माहौल है। मौलाना ने आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही है। ज्ञापन में लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की। इसके मद्देनजर बृहस्पतिवार शाम से ही शहर में चौकसी बढ़ा दी गई थी। शुक्रवार को सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। श्यामगंज मंडी वाले रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ भारी फोर्स तैनात की गई। सैलानी इलाका बंद रहा। दोपहर होते-होते लोग घरों से निकलने लगे। जुमे की नमाज के बाद लोग जुलूस के रूप से नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले।

शिवली में पकड़ा गया किशोरी का रेपिस्ट हत्यारा

» मोबाइल और तमंचा बरामद, पुलिस फायरिंग में आरोपी ढेर हुआ ज़मीन पर

» अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश, हत्या के कारणों की पड़ताल जारी

प्रेम प्रसंग के चलतं युवती की हत्या, झाड़ियों में मिला शव

» शिवली कोतवाली के मैथा लालपुर गांव का मामला

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र के लालपुर शिवराजपुर में चर्चित किशोरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी करन भदौरिया आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया।

पुलिस ने शुक्रवार भोर में केसरी निवादा नहर पुलिया से उसे दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने मृतका का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल तमंचा छिपाने की बात स्वीकार की। बरामदगी के लिए ले जाने पर आरोपी ने पुलिस पर फायर झोंक दिया और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे आरोपी करन के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को सीएचसी शिवली में भर्ती कराया गया है।आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और मृतका का मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस टीम का कहना है कि आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें आरोपी घायल हुआ।

गुरुवार को लालपुर शिवराजपुर गांव में किशोरी का शव मिलने के बाद मृतका के पिता की तहरीर पर करन भदौरिया समेत कई लोगों पर हत्या, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

पुलिस हत्या की वजह की पड़ताल में जुटी है और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

सेवा पखवाड़ा को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब होगी सख्त कार्रवाई

» ऑनलाइन कोर्स पूरे न करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

» चौंकाने वाले आंकड़ों से शिक्षा विभाग में हड़कंप

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राज्य सरकार के 'सेवा पखवाड़ा' अभियान को हल्के में लेना अब शिक्षकों को भारी पड़ सकता है। ऑनलाइन कोर्स पूरे न करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इस लापरवाही से नाराज होकर, स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सख्त चेतावनी जारी की है।अभियान के दौरान सभी शिक्षाकर्मियों को आई-गोट (आईजीओटी) पोर्टल पर कम से कम पांच कोर्स पूरे करना अनिवार्य था। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली।

बड़ी संख्या में शिक्षक इस जिम्मेदारी से पीछे हट गए। इससे न केवल अभियान की गंभीरता पर सवाल उठे हैं बल्कि विभागीय लापरवाही भी उजागर हो गई है।आंकड़े बताते हैं कि लगभग ढाई लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने एक भी कोर्स पूरा नहीं किया। वहीं, मुश्किल से कुछ हज़ार शिक्षकों ने 10 या उससे ज्यादा कोर्स किए। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षाकर्मी भी हैं जिन्होंने केवल 2 से 4 कोर्स पूरे किए। इन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखते हुए महानिदेशक ने सभी डायट प्राचार्यों, जिला विद्यालय निरीक्षकों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाई है।महानिदेशक ने साफ किया है कि मिशन कर्मयोगी के तहत निर्धारित समयसीमा में न्यूनतम पांच कोर्स पूरे करना अनिवार्य है। इस आदेश की अवहेलना करने वाले शिक्षकों पर अब कठोर कार्रवाई तय है। विभागीय स्तर पर भी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

डीएम की पैनी नजर: ईवीएम वेयरहाउस में सुरक्षा-व्यवस्था पर जोर

» साफ-सफाई व सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही न हो बोले जिलाधिकारी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मंगलवार को ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डीएम ने वेयरहाउस में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों, साफ-सफाई और रखरखाव का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ईवीएम वेयरहाउस संवेदनशील स्थान है, इसलिए यहां हर व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहनी चाहिए। नियमित अंतराल पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ-सफाई और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, परियोजना निदेशक वीरेंद्र सिंह, वेयरहाउस इंचार्ज देवेंद्र कुमार वर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी गिरवर प्रसाद समेत सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। वहीं राजनीतिक दलों से बीजेपी के श्याम बिहारी शुक्ला, श्यामू शुक्ला, समाजवादी पार्टी के शेखू खान व बृजमोहन यादव, कांग्रेस से गोविंद यादव व बालकेशन, कम्युनिस्ट पार्टी से राम औतार भारती और आम आदमी पार्टी से रोहित कुमार यादव भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

नवरात्र पर छात्राओं को मिला आत्मनिर्भरता का मंत्र

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। नवरात्र पर्व पर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज-5 अभियान के तहत गजनेर थाना पुलिस ने सोमवार को फुलेश्वर महादेवी इंटर कॉलेज, रुरुआ में छात्राओं को महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान थाना प्रभारी जनार्दन सिंह सहित महिला उपनिरीक्षकों और सिपाहियों ने छात्राओं के साथ संवाद किया।

» मिशन शक्ति फेज-5 के तहत गजनेर पुलिस ने किया जागरूकता अभियान

» लड़कियों को हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी, कानून और अधिकारों पर हुई चर्चा

पुलिस टीम ने छात्राओं को नारी सुरक्षा से जुड़े 1090, 1076, 1930, 1098, 112 और 181 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और बताया कि किसी भी समस्या या आपात स्थिति में इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। साथ ही छात्राओं को अपने मोबाइल नंबर साझा करते हुए कहा कि किसी भी परेशानी की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं।अभियान में छात्राओं को यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों को पहचानें और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लेने में झिझकें नहीं।कार्यक्रम में छात्राओं को संदेश दिया गया कि वे शिक्षा, कौशल और आत्मविश्वास के बल पर आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। थाना प्रभारी ने कहा कि नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मिशन शक्ति अभियान इसी दिशा में एक मजबूत कदम है।अभियान के दौरान महिला दारोगा और महिला सिपाहियों ने छात्राओं को अपने अनुभव साझा कर प्रेरित किया। पुलिस ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि कानून उनके साथ है और यूपी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर है।

'एक उम्मीद' के मंच से बंधा भरोसे का रिश्ता महिलाएं बनी परिवार का हिस्सा

» नन्हे-मुन्नों को शिक्षा सामग्री वितरित कर बच्चों के चेहरे खिले

सदस्यों को संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंप, मजबूत किया गया 'एक उम्मीद' परिवार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। रनिया विधानसभा क्षेत्र के अंबरपुर गांव में गुरुवार को एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष सविता कुरील ने की और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष का0 ग्रा0 पवन चौहान मौजूद रहे।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कृष्णकांत ने सैकड़ों महिलाओं को संगठन की सदस्यता दिलाई और उन्हें पहचान पत्र वितरित कर 'एक उम्मीद परिवार' से जोड़ा।बैठक में कई नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। रणवीर सिंह को सलाहकार मंत्री, श्रीमती रूबी देवी को कार्यालय प्रभारी, जबकि श्रीमती नीरज सिंह, श्रीमती देवकी देवी और श्रीमती रीमा देवी को रनिया विधानसभा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, सदस्य पद पर साधना सिंह,रूबी पाल,शिखा सिंह,मालती देवी,निर्मला तिवारी,रामकांती,पान कुमारी,राहुल कुमार,सरमन देवी और सुमन देवी को जोड़ा गया। सभी नए सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

इस मौके पर संगठन की ओर से ग्राम पंचायत अंबरपुर के नन्हे-मुन्ने बच्चों को शिक्षा सामग्री भी वितरित की गई, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पवन चौहान, महामंत्री राजेंद्र पाल, प्रभारी उमेश भार्गव, मीडिया प्रभारी आर्यन शर्मा, रनिया विधानसभा अध्यक्ष कृष्णकांत, ग्राम प्रधान संजय पाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।

शादी के मंडप में हाईवोल्टेज ड्रामा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बाराबंकी। जनपद के बंकी कस्बे के उत्तर टोला मोहल्ले में बुधवार रात एक शादी समारोह फिल्मी ड्रामे में बदल गया। मंडप में बैठे दूल्हे के सामने ही दुल्हन के ब्वायफ्रेंड ने उसकी मांग भर दी। इस घटना से माहौल गरमा गया और हंगामे के बीच दूल्हा बारातियों समेत बिना दुल्हन के वापस लौट गया।

» दुल्हे के सामने ब्वाय फ्रेंड ने दुल्हन की मांग भरी

» दहेज विवाद का आरोप लगाकर हुआ हंगामा, लौट गई बारात

मोहिनी नामक युवती की शादी विकास सोनी निवासी लखनऊ से तय हुई थी। बुधवार को बारात धूमधाम से पहुंची और रस्में शुरू हुईं।

इसी बीच दूल्हे पक्ष ने दहेज में डेढ़ लाख रुपये नकद और डेढ़ तोले सोने की अंगूठी की मांग कर दी। लड़की पक्ष ने इसे देने से इनकार किया। विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। हंगामे के बीच मोहिनी ने अपने ब्वायफ्रेंड शिवांश (जो उसकी बहन का देवर भी है) से शादी का प्रस्ताव रखा।

मौके की नजाकत देखते हुए शिवांश ने सभी के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। यह नजारा देखकर मंडप में अफरा-तफरी मच गई और बारातियों ने विरोध शुरू कर दिया।

पुलिस की दखल से मामला निपटा

स्थिति बिगड़ने पर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शिवांश को हिरासत में ले लिया। हालांकि देर रात तक दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।लड़की पक्ष का कहना है कि दूल्हा उन्हें पसंद नहीं था और ऊंची दहेज की मांग कर रहा था।

दूल्हे के पिता का आरोप है कि लड़की वालों ने खुद पैसों की मांग की और शादी तोड़ने की योजना पहले से बनाई थी।

चर्चा का विषय बनी घटना

यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे प्रेम प्रसंग और दहेज विवाद से जुड़ा मामला मान रहे हैं। मंडप में हुए इस हाईवोल्टेज ड्रामे की गूंज सोशल मीडिया पर भी देखी जा रही है।

टीईटी प्रकरण में शिक्षक संगठन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

क्या टेट परीक्षा से डर रहे हैं शिक्षक ? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार देगी कोई समाधान

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर/लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर दिए गए फैसले से शिक्षकों में भारी रोष है। शिक्षकों के लिए तय की गई टीईटी के नियम की बाध्यता उनके गले की फांस बन गई है। शिक्षक महकमा संवैधानिक दायरे में रहकर कानूनी लड़ाई की तैयारी में लगा हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के निर्णय से प्रभावित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। प्रदेश सरकार के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है जबकि कुछ और शिक्षक संगठन भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में लिए गए निर्णय से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है वह स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब उन सभी बेसिक शिक्षकों को भी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है जिन्हें आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। ऐसे में 15-20 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक भी अब नौकरी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस नियम से एक-दो शिक्षक नहीं बल्कि लाखों शिक्षक तनाव में आ गए हैं। अगर शिक्षक नियमों में उलझे तो बहुतों की नौकरी दांव पर लग जाएगी।

संकट में फंसे शिक्षक, कैसे हो समाधान-

शिक्षकों का कहना है कि इस निर्णय ने शिक्षकों का चैन छीन लिया है। एक तो सरकार ने शिक्षकों पर सरकारी कामों का बोझ लाद रखा है ऊपर से टीईटी का नियम उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। सबसे बड़ी समस्या उन शिक्षकों के सामने है जिन्होंने 12वीं के बाद बीटीसी कर नौकरी पाई थी। इतना ही नहीं मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त शिक्षक, इंटरमीडिएट के साथ बीटीसी करने वाले गुरुजन और वह शिक्षक भी शामिल हैं जो स्नातक तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके।

जब कुछ शिक्षकों के पास स्नातक की डिग्री ही नहीं है तो वे टीईटी कैसे देंगे? नौकरी और पदोन्नति पर संकट से परेशान शिक्षकों का कहना है कि फैसले के अनुसार जिन शिक्षकों ने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है उन्हें दो वर्षों के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा नौकरी चली जाएगी। वहीं जिन शिक्षकों के सेवानिवृत्ति में मात्र पांच साल बचे हैं उन्हें बिना टीईटी पास किए पदोन्नति नहीं मिलेगी। यह स्थिति उन शिक्षकों के लिए और भी अधिक परेशान करने वाली है जिन्होंने जीवन के सुनहरे साल बच्चों को शिक्षित करने में लगा दिए और अब बुढ़ापे की देहरी पर खड़े होकर असुरक्षा की खाई में धकेले जा रहे हैं।

मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो फिर टीईटी क्यों

कानपुर देहात समेत पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक इस फैसले से आहत हैं। शिक्षकों का मानना है कि यह आदेश उनके जीवन के अधिकार और आजीविका के अधिकार का हनन है।

शिक्षक संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर कानूनी लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था को बाधित नहीं करना चाहते लेकिन अपने भविष्य और परिवार की आजीविका बचाने को संघर्ष करना मजबूरी है। अधिकतर शिक्षक आरटीई के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, इसके बावजूद टीईटी का बोझ सिर पर लादा जा रहा है। पहले बीएड को प्राथमिक शिक्षा से अलग किया गया और अब इस बाध्यता ने परेशानी खड़ी कर दी है। भर्ती के दौरान पहले शिक्षकों को बीएड के साथ विशिष्ट बीटीसी भी करना था, कुछ ने ब्रिज कोर्स भी किया, नियम बदलते गए और शिक्षक उनमें ढलते गए लेकिन अब नौकरी पर बात आ गई है। शिक्षकों का कहना है कि जिस शिक्षक ने दो दशक से ज्यादा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाया, जो सुबह से शाम तक चॉक-डस्टर में लिपटा रहा, अब वही शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए अदालत की चौखट पर खड़ा है। क्या यह न्यायसंगत है कि जो कल तक गुरु कहला रहा था, आज अपनी योग्यता पर सवालों से घिरा है। सरकार को इस बारे में सोचना होगा।

एक शिक्षामित्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आखिर शिक्षक टेट से डर क्यों रहे रहें हैं जब 50 और 55 साल के शिक्षामित्रों ने टेट और सुपर टेट पास किया तो शिक्षक तो शिक्षामित्रों से योग्य हैं और सबसे बडी बात आज जमाना तेजी से बदल रहा है हर किसी को अपडेट होते रहना है, अगर सही तरीके से शिक्षा देनी है तो अपडेट तो होना ही पड़ेगा और आपको तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने आपकी एक से डेढ लाख सैलरी बहाल करके ही टेट का मौका दिया है जबकि शिक्षामित्रों से तो सैलरी रोककर टेट और सुपर टेट निकालने को कहा गया था इसलिए आप सभी यह साबित कर दो। आप लोग भी शिक्षामित्रों की तरह योग्य हो आपको मांग करनी चाहिए कि हम पर भी शिक्षामित्रों की तरह टेट के बाद सुपर टेट और लगाया जाए जिससे समाज मे संदेश जाए हां हम योग्य हैं। जब शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पद से हटाया था तब आप लोग योग्यता की दुहाई दे रहे थे अब आपकी योग्यता कहा गई।

क्षय रोग विभाग के कार्मिकों की समस्याओं का कराएंगे निस्तारण

» प्रदेश स्तर से संघ की सभी समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा-सागर पाण्डेय

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश टीबी मेल हेल्थ विजिटर्स संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सागर पाण्डेय ने पदाधिकारियों संग लखनऊ में राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेन्द्र भटनागर से मुलाकात कर उनको प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

अधिकारी को कार्यकारिणी का आधिकारिक पत्र भी सौंपा। सागर पाण्डेय ने बताया कि अधिवेशन और कार्यकारिणी गठन की जानकारी के साथ ही मांगपत्र दिया है। प्रदेश स्तर से संघ की सभी समस्याओ का निस्तारण किया जायेगा । स्टेट टीबी ऑफिसर ने जल्द ही टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग की अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाने और निकट भविष्य में संवर्ग को जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है।

प्रांतीय महामंत्री एके पाण्डेय, कोषाध्यक्ष गौरव पोरवाल, उपाध्यक्ष कमलेश सिंह, सयुंक्त मंत्री लोकेश श्रीवास्तव, सयुंक्त मंत्री योगेश शाक्य, मीडिया प्रभारी/समन्वयक मानस पाण्डेय संरक्षक के रूप में रवि कुमार मिश्रा आदि रहे। संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने मिलकर अपने संघ के वरिष्ठ संरक्षक रवि कुमार मिश्रा का स्वागत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

रामपथ पर अतिक्रमण देख नाराज डीएम, एक्शन शुरू

» डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ दिया है। सहादतगंज से लता चौक तक 13 किलोमीटर लंबे रामपथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम की टीम ने मोर्चा संभाला। अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा की अगुवाई में जब बुलडोज़र चला तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दुकानों से कुर्सियां, मेज, फ्रिज और तमाम सामान ट्रॉलियों में भरकर हटाए गए।

प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण से यातायात बाधित हो रहा था और आम जनता को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही थीं। बीते हफ्ते ही व्यापारियों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन समयसीमा खत्म होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई 8 अक्टूबर तक लगातार चलेगी और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।लेकिन बड़ा सवाल यह है–क्या यह कार्रवाई निष्पक्ष हैरामपथ को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल स्वागत योग्य है, लेकिन शहरवासियों में यह चर्चा गर्म है कि आखिर प्रशासन का बुलडोज़र सिर्फ चुनिंदा मार्गों पर ही क्यों चल रहा है रिकाबगंज से चौक, चौक से रीडगंज, चौक से फतेहगंज, नाका मकबरा और कसाबबाड़ा जैसे इलाकों में अतिक्रमण की स्थिति रामपथ से कहीं ज्यादा भयावह है। वहां पैदल निकलना तक मुश्किल है, लेकिन अब तक इन क्षेत्रों में कोई ठोस अभियान क्यों नहीं चलाया गया?

स्वराज इंडिया का सवाल प्रशासन से

-क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ रामपथ तक सीमित है, जबकि बाकी इलाकों में आम जनता रोजाना त्राहिमाम करती है?

-क्या यह अभियान धार्मिक व पर्यटन महत्व वाले मार्ग को सुंदर दिखाने की कवायद भर है या फिर वास्तव में पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की गंभीर मंशा है?

रामपथ पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलने से प्रशासन ने एक कड़ा संदेश जरूर दिया है, लेकिन जब तक रिकाबगंज, चौक, रीडगंज और कसाबबाड़ा जैसे इलाकों पर भी यही सख्ती नहीं दिखाई जाएगी, तब तक यह कार्रवाई आधी-अधूरी और सवालों के घेरे में ही रहेगी।

सख्ती और पारदर्शिता का नाम-डीएम निखिल टीकाराम फुंडे

अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने जिस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसने प्रशासनिक सख्ती की नई मिसाल पेश की है। साफ संदेश है कि जनता की सुविधा से बड़ा कोई हित नहीं।रामपथ को अतिक्रमण मुक्त कराने से लाखों श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक आसानी से आवाजाही कर पाएंगे।

व्यापारियों को पहले चेतावनी, फिर समयसीमा और अब निर्णायक एक्शन-यह प्रशासनिक पारदर्शिता और दृढ़ निश्चय का उदाहरण है।सामान को ट्रॉलियों में भरकर सुरक्षित जगह भिजवाना दिखाता है कि कार्रवाई कठोर जरूर है, लेकिन अमानवीय नहीं। फुंडे के नेतृत्व में चल रही यह मुहिम अयोध्या को स्वच्छ, व्यवस्थित और यातायात की दृष्टि से बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यही वजह है कि जनता अब उम्मीद कर रही है कि डीएम की यह सख्ती पूरे शहर में देखने को मिलेगी।

वॉटर लाइन है नहीं नगर निगम भेज रहा जलकर वसूली

» जल आपूर्ति सुविधा के बिना जलकर व गृहकर वसूली पर विवाद गहराया

» जनता की नाराजगी पर नगर आयुक्त कैम्प छोड़कर चले गए

» सीएम कार्यालय में हुई शिकायत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या नगर निगम पर बिना जल आपूर्ति सुविधा दिए जलकर और गृहकर वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस संबंध में डॉ. रजनीश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर नगर निगम की कार्यवाही को जनविरोधी और असंवैधानिक बताया है।शिकायत में कहा गया है कि

जल्द ही जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी सुनिश्चित-नगर आयुक्त

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नए परिसीमन क्षेत्रों में विकास कार्यों और जल आपूर्ति व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। कर वसूली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। अधिकारियों का तर्क है कि निगम को कर मिलने से ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जुटाए जाते हैं। वहीं, नगर आयुक्त ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और जल्द ही जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिसीमन के बाद नगर निगम में शामिल किए गए कई गांवों में अभी तक नागरिकों को जल आपूर्ति की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा जलकर और गृहकर की वसूली की जा रही है। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन बताई गई है।

डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि–जब तक जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध न हो, जलकर वसूली पर रोक लगाई जाए।पूर्व में वसूले गए जलकर की जांच कर उसकी वापसी या समायोजन किया जाए। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।इस बीच जनता में भी गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बिना गलती के फांसी दी जा रही है। गुरुवार को नाका पर आयोजित कैम्प में जब नागरिकों ने सवाल उठाए तो नगर आयुक्त मौके से कैम्प छोड़कर चले गए।

अयोध्या के व्यापारियों को भरोसे का संदेश दे गए नितिन अग्रवाल

» मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि विकास, पारदर्शिता और सख्ती योगी सरकार की प्राथमिकता

» बिहार चुनाव पर जताया विश्वास

» उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने किया भव्य स्वागत

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अयोध्या प्रवास के दौरान स्पष्ट किया कि सरकार जनता और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ही विकास की गारंटी है और जनता ने लालू यादव के जंगलराज को कभी माफ नहीं किया। मंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जनता से संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखने का आह्वान किया।

अग्रवाल सभा के कार्यक्रम में शामिल होकर व्यापारियों को जीएसटी सुधारों की जानकारी दी और कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। मंत्री का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू के नेतृत्व में व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया और कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा।

आबकारी विभाग पर सख्त निर्देश

मंत्री ने साफ कहा कि अगर किसी दुकान पर तय समय से बाहर शराब बिक्री पाई गई तो जिम्मेदार इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा और आबकारी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अयोध्या से मंत्री नितिन अग्रवाल ने विकास, पारदर्शिता और सख्ती का जो संदेश दिया है, उसने आम जनता और व्यापारियों दोनों में विश्वास की नई लहर पैदा की है।

अंतिम चरण में श्री राम मंदिर निर्माण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य अपने अंतिम सोपान पर है। आने वाली 25 नवंबर 2025 को रामलला के दिव्य धाम में भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित होगा। यह अवसर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक गौरव और सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक बनने जा रहा है।अक्टूबर के अंत तक मंदिर परिसर का लगभग 70 प्रतिशत भाग हरियाली से ढकने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्ष, लताएँ और पुष्पों की सुगंध से मंदिर क्षेत्र को स्वर्गिक आभा प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुगमता और अनुशासन बनाए रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार, 25 वॉच टावर

और अत्याधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे। कुबेर टीला और राम दरबार जैसे संवेदनशील स्थलों पर दर्शन सीमित संख्या में ही कराए जाएंगे।अक्टूबर से मंदिर परिसर और आसपास के मठ-मंदिरों में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ध्वजारोहण के उपरांत मंदिर परिसर में भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण आरंभ होगा, जिसे मार्च 2026 तक पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है। यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजनों का वैश्विक मंच सिद्ध होगा। राम मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। यह प्रकल्प समूचे राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रधर्म के पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर युगों-युगों तक प्रकाशमान रहेगा।

श्रीरामं रघुनाथं वन्दे लोकाभिरामं।
(मैं उन श्रीराम का वंदन करता हूँ, जो रघुकुलनायक और सम्पूर्ण लोक के लिए मनोहर हैं।)

विवादः अब बीएसए ने महिला शिक्षक को भी किया सस्पेंड

लंबे समय से चल रही थी गैर हाजिर अवंतिका गुप्ता

» कार्यालय संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और प्रधानाध्यापक के बीच विवाद के चलते चर्चा में आई शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। बीएसए ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की है।

बता दें कि अवंतिका गुप्ता वही शिक्षिका हैं, जिन्हें लेकर प्रधानाध्यापक और बीएसए के बीच विवाद हुआ था। स्कूल के बच्चों ने भी कैमरे पर कहा था कि वो स्कूल नहीं आती हैं। जब आती भी हैं तो देर से आती हैं और जल्दी चली जाती हैं। शिक्षिका का वेतन रोकने का आदेश भी जारी हो चुका है।

निलंबन आदेश में बताया गया है कि शिक्षिका को बीएसए में पेश होकर 21 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक स्कूल में अनुपस्थित रहने को लेकर जवाब देने का निर्देश दिया गया था। वह 23 सितंबर को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुईं। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रिंसिपल ने बेल्ट से बीएसए की पिटाई की थी। इस घटना के बाद पूरी कहानी सामने आई। प्रिंसिपल बृजेन्द्र वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा ने बताया कि उनके पति को एक शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने के लिए बाध्य किया जाता था। वह लगातार इसके लिए मना कर रहे थे।

इसलिए बीएसए अखिलेश सिंह उनके पति को परेशान कर रहे थे। पहले उनके पति से स्कूल में हुए कार्यों का तीन साल का ब्यौरा मांगा गया। जब उन्होंने ब्यौरा दे दिया तो दस साल का ब्यौरा मांगा गया। जब वह भी दे दिया तो दबाव बनाने के लिए बीएसए आफिस बुलाया गया। वहां कहासुनी हुई और उनके पति ने गुस्से में बीएसए की पिटाई कर दी।

इससे पहले गुरुवार सुबह भाजपा की महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य स्कूल पहुंची। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों से ईंट से क्लास का ताला तु?वाया। इसके बाद उन्होंने बच्चों से प?ने के लिए कहा। इसके बावजूद बच्चों ने प?ने से इनकार कर दिया। विधायक आशा मौर्य ने कहा कि प्रधानाध्यापक की कोई शिकायत थी तो वह सही ढंग से अपनी बात रखते। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि प्रधानाध्यापक ने बेल्ट निकाल कर पीटा है, यह बेहद गलत है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को बेल्ट से पीटने के आरोपी प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा को बुधवार सुबह निलंबित कर दिया गया। उधर, नदवा विद्यालय के बच्चों ने बुधवार सुबह स्कूल के बाहर अभिभावकों के साथ शिक्षिका अवंतिका के खिलाफ नारेबाजी की और बृजेंद्र वर्मा को बहाल करने की मांग उठाई। विरोध के कारण स्कूल में पढ़ाई ठप रही। बीएसए ने बुधवार को एक शिक्षक को विद्यालय में भेजा, लेकिन अभिभावकों ने उन्हें पढ़ाने नहीं दिया।

नदवा विद्यालय में अब राजनीति हो रहीः बीएसए

बीएसए सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह ने बयान दिया कि प्राथमिक विद्यालय नदवा में अब राजनीति हो रही है। प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। बुधवार सुबह एक दूसरे शिक्षक को स्कूल भेजा गया था। ग्रामीणों ने उन्हें पढ़ाने नहीं दिया। वह प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीणों को समझाकर जल्द स्कूल में पढ़ाई शुरू कराएंगे।

आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर निकले उपद्रवी

बरेली में बवालः तोड़फोड़ के बाद पथराव, लाठीचार्ज

» मौलाना तौकीर नजरबंद, बयान के बाद हुआ हंगामा।

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

बरेली। बरेली में शुक्रवार को बवाल हो गया। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां ओर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल पड़े और नारेबाजी करते हुए इस्लामिया ग्राउंड व खलील स्कूल चौक की ओर बढ़े। जैसे ही भीड़ इन इलाकों में पहुंची, माहौल गर्मा गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन लोग बेकाबू हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

शुक्रवार को नमाज खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते हुए खलील तिराहा पहुंचे। जब इन लोगों ने इस्लामिया की ओर जाने का प्रयास किया, तो मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस के रोकने पर भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने कम से कम दो मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की और एक दुकान को भी निशाना बनाया। स्थिति को नियंत्रण में लाने और उपद्रव को शांत करने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई।

उपद्रव वाले क्षेत्र, खलील तिराहा के करीब 200 मीटर के दायरे में चप्पलें, जूते और पत्थर बिखरे पड़े दिखाई दिए, जो बवाल की गंभीरता को दर्शाते हैं। हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही डीआईजी अजय साहनी, एसपी सिटी सहित पुलिस और प्रशासनिक विभाग के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके में फ्लैगमार्च किया है ताकि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

साथ ही मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर लिया गया है। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के एलान के बाद से शहर में गहमागहमी का माहौल है। मौलाना ने आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही है।

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका

सिखों पर की गई टिप्पणी मामले में चुनौती याचिका रद्द

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

प्रयागराज। रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं अब स्पेशल कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने दिया है।

यह मामला सितंबर 2024 का है। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ था।

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर उन्होंने अदालत का रुख किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की जिसे 21 जुलाई 2025 को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अब इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। दलील दी गई है कि वाराणसी अदालत का आदेश गलत, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लिहाजा जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है तब वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए।

महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किया विधान सभा का भ्रमण

अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत पर दी विस्तृत जानकारी

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। कानपुर के महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं का एक दल विधानसभा भ्रमण हेतु प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनसे आत्मीय संवाद किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गहन जानकारी साझा की।

महाना ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एक विधायक अपनी जनता से सबसे निकट जुड़ा होता है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में काम करना होती है। उन्होंने कहा कि पहली बार चुनाव जीतना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, किंतु लगातार जनता का विश्वास अर्जित करना कहीं अधिक कठिन कार्य है। यही किसी जनप्रतिनिधि की असली पहचान है।

विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को विधायिका की भूमिका और महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायिका ही वह सर्वोच्च मंच है, जहां जनता की आवाज उठती है, समस्याओं पर चर्चा होती है और उनके समाधान के लिए कानून बनाए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका कभी खराब नहीं हो सकती, केवल उससे जुड़े व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों से विमुख हों तो उसकी छवि प्रभावित हो सकती है।

महाना ने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में जनता से जुड़े प्रतिनिधि ही प्रदेश की दिशा और गति तय करते हैं। विधायक अपने क्षेत्र की नब्ज पहचानता है और उसी अनुभव के आधार पर प्रदेश व देश के लिए नीतियां तैयार होती हैं।

छात्रों से संवाद करते हुए महाना ने आग्रह किया कि वे इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने घर-परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

भ्रमण के दौरान छात्रों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली का निकट से अवलोकन किया और कई जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे। महाना ने उनके उत्साह और जागरूकता की सराहना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि यही युवा भविष्य में लोकतंत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।